Government to Assam during last three years, till date is given in the statement *(sec* below).

(b) It is proposed to earmark 10% of the budget allocation to the North-Eastern States.

Statement -

Release of funds under Rural Development Programmes to Assam during 1995-96, 1996-97, 1997-98 and 1998-99 (Till date)

(Rs. in lakhs)

SI No.	Name of the Scheme	Release of funds by Central Govt, to Assam			
		1995-96	1996-97 ,	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6
1.	JRY	7719.76	3186.83	5524.15	4011.71
2.	EAS	8020.00	10820.00	8592.00	2488.00
3.	MWS	1143.53	1054.14	1210.22	723.35
4.	IAY	2656.32	3157.45	2931.07	3347.27
5.	1RDP	1537.96	1066.76	1425.63	1163.68
6.	DWCRA	158.85	180.89	136.16	118.88
7.	TRYSEM	81.57	105.45	104.33	71.22
8.	TOOLKITS	171.00	114.85	82.85	93.97
9.	NSAP	471.83	697.94	742.41	206.33
10.	ARWSP	2245.00	2353.57	2376.52	2485.48

*Including UNICEF

बंजर भूमि के, विकास हेतु धनराशियों की सी0 ए0 जी0 द्वारा लेखा परीखा

1208. **श्री ओंकार सिंह लखावत :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सी0 ए0 जी0) ने बंजर भूमि के विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए सरकार द्वारा आबंटित धनराशियों के संबंध में लेखा-परीक्षा की हैं, यदि हां, तो ऐसी लेखा-परीक्षा किस-किस वर्ष के लिए की गई हैं और यदि नहीं, तो उसके-क्या कारण हैं,

(ख) क्या सरकार ने बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का पुनरीक्षा, निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करने के लिए कोई कारगर व्यवस्था की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, और

(ग) राजस्थान में बंजर भूमि विकास हेतु आवंटित धनराशियां प्राप्त करने वाले उन संगठनों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में सी0 ए0 जी0 द्वारा लेखा-परीखा की गई और क्या लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आपत्तियां दर्ज की गई हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा आर0 पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां । बंजरभूमि विकास विभाग की स्थापना जुलाई, 1992 में की गई थी । विभाग के कार्यक्रमों की लेखा-परीक्षा प्रधान निदेशक, लेखा-परीक्षा, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, के कार्यालय के द्वारा की जाती हैं । अभी तक लेखा-परीक्षा, 31 मार्च 1997 को समाप्त अवधि तक के लिए की गई हैं ।

(ग) राजस्थान में वित्तपोषित किसी भी संगठन के सम्बन्ध में कोई भी लेख-परीक्षा पैरा विभाग में लम्बित नही हैं ।

NGOs blacklisted by Capart

1209. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether nearly 350 Non-Governmental Organisations (NGOs) were blacklisted by Council for Advancement